

एस. एस. संधवालिया, सी. जे. सुरिंदर सिंह और आई. एस. तिवाना, जे.जे.

JOG DHIAN VINOD KUMAR -Petitioner.

बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य, - उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1972 का 3848।

9 अगस्त, 1982।

भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 19 - पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम (1972 का XIX) - पंपिंग सेटों पर पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ बिक्री कर की वसूली - क्या अनुच्छेद 19 के विपरीत है।

यह माना गया कि पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1972 के आधार पर रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव के साथ पंपिंग सेटों पर बिक्री कर की वसूली सही है और भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 19 के विपरीत नहीं है।

(सेवा 6)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि निम्नलिखित राहत दी जाए: -

- (i) सर्विओररी रिट की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, जिसमें आक्षेपित आदेश, अनुबंध के 'ए' से संबंधित प्रतिवादियों के रिकॉर्ड मांगे गए हों और उसी के अवलोकन के बाद, अनुलग्नक 'ए' को रद्द कर दिया जाए;
- (ii) पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (हरियाणा संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1972 को घोषित करना। 1972 की धारा 19 संविधान के दायरे से बाहर है;
- (iii) कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जो यह माननीय न्यायालयइस मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, जारी किया जाए।
- (iv) एक अंतरिम आदेश जारी किया जाए जिसमें याचिकाकर्ता पर कर की वसूली पर रोक लगाते हुए कर निर्धारण आदेश, अनुलग्नक 'ए' द्वारा रिट याचिका का अंतिम निर्णय होने तक रोक लगाई जाए;
- (v) याचिकाकर्ता को याचिका की लागत की अनुमति दी जाए।

आर. एन. नरूला के साथ पी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एस. सैनी।

उत्तरदाताओं के लिए पी.एस.दुहन, डी.ए.जी., हरियाणा।

निर्णय

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.

1. (पूर्ण पीठ द्वारा स्पष्टीकरण के लिए तैयार किया गया सार्थक प्रश्नयह है कि-

"क्या पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1972, (1972 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19) क्या यह भारत के संविधान के दायरे से बाहर है, जहां तक यह गेहूं-थ्रेसर डिस्क, पंपिंग सेट पर बिक्री कर को पूर्वव्यापी रूप से लागू करता है?

2. इस मामले के उतार-चढ़ाव भरे इतिहास ने इस मुद्दे को जन्म दिया है, भले ही संक्षेप में। इस रिट याचिका को पूरे एक दशक पहले पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19) द्वारा पंपिंग सेटों (जो याचिकाकर्ता-फर्म द्वारा विपणन किया जा रहा था) पर पूर्वव्यापी बिक्री कर लगाने को चुनौती देने के लिए प्राथमिकता दी गई थी। इसी तरह की मांग उठाने वाली कई अन्य याचिकाओं के साथ, यह रिट याचिका भी खंडपीठ द्वारा विचार के लिए आई, जिसने 15 फरवरी, 1973 के अपने स्पष्ट आदेश द्वारा आरंभ में उल्लिखित प्रश्न को पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय के लिए भेज दिया।

3. 2 अगस्त, 1976 को सभी संबंधित रिट याचिकाएं इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं। तथापि, इस बीच, हरियाणा सरकार ने 4 जून, 1974 को जारी किए गए अनुदेशों द्वारा निदेश दिया था कि डिस्क और डिस्क की बिक्री के लिए बिक्री कर लगाने से छूट दी जाए। नतीजतन, जिन रिटों में गेहूं थ्रेसर और डिस्क पर बिक्री कर लगाने की एकमात्र चुनौती थी, वे निरर्थक हो गए थे, जिसमें अन्य विवाद उपलब्ध थे, उन्हें योग्यता के आधार पर निर्धारण के लिए डिवीजन-वी बेंच को वापस भेज दिया गया था।

4. वर्तमान रिट याचिका में चुनौती को पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 19 पर रखा गया था। हालांकि, पूर्ण पीठ के समक्ष पहले की सुनवाई के समय, आपातकाल की घोषणा के कारण, उक्त अनुच्छेद का संचालन निलंबित कर दिया गया था। नतीजतन, यह निर्देश दिया गया था कि वर्तमान रिट याचिका होगी

जोग ध्यान विनोद कुमार बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य (एस.
एस. संधावालिया, सी.जे.)

लंबित रखा गया लेकिन याचिकाकर्ता के पक्ष में दिए गए स्थगन आदेश को हटा दिया गया। अब यह मामला हमारे सामने ऐसा ही है।

5. इस फैसले पर पहले के पूर्वाग्रहों की विस्तृत चर्चा के सिद्धांत पर किसी भी तरह का बोझ डालना पूरी तरह से अनावश्यक लगता है। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि प्रतिवादियों की ओर से बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड में इस कोर, टी के डिवीजन बेंच के फैसले पर दृढ़ भरोसा रखा गया था। बहुत। हरियाणा राज्य और दूसरा (1)। पीठ द्वारा निर्णय के लिए तैयार की गई पंद्रह रिट याचिकाओं में सामान्य प्रश्ननिम्नानुसार था: -

"क्या हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 2 (सी) में 'डीलर' की

परिभाषा को 7 सितंबर, 1955 से दिया गया पूर्वव्यापी प्रभाव, इसके अन्तर्गत धारा की उप-धारा (3) के पहले खंड के आधार पर असंवैधानिकता से ग्रस्त है? सिद्धांत पर एक विस्तृत चर्चा के बाद और अंतिम न्यायालय के बाध्यकारी उदाहरण पर भरोसा करते हुए, इसका उत्तर नकारात्मक में प्रस्तुत किया गया था और यह माना गया था कि कानून द्वारा पूर्वव्यापी रूप से दिया गया कथन वैध था।

6. उदाहरण की उपरोक्त अभेद्य दीवार का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री आर. एन. नरूला ने यह रुख अपनाया कि वह बिड़ला कॉटन एसपीइनिंग और वीविंग मिल्स मामले (सुप्रा) में अनुपात को कोई सार्थक चुनौती देने में असमर्थ थे, और न ही इस बात से इनकार किया गया था कि, यह अब उत्तरदाताओं के पक्ष में हमारे सामने आने वाले प्रश्न को कवर करेगा। तदनुसार, बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स के मामले में दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए, हम शुरू में पूछे गए प्रश्न का उत्तरनकारात्मक में देते हैं, यह मानते हुए कि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ बिक्री-कर का अधिरोपण वैध था।

7. श्री आर. एन. नरूला ने तब स्पष्ट रूप से कहा था कि वास्तव में अब कोई अन्य व्यक्तिजीवित नहीं बचा है। इसलिए, रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए बहुत ही निष्पक्ष रुख को देखते हुए हम उन पर लागत का बोझ डालने से इनकार करते हैं-

Surinder Singh, J.—I agree.

एच.एस.बी.

(1) (1979) 43 एसटीसी 158।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा